ont>

Title: Need to review the decision to disinvest Public Undertakings.

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौप कर देश के गरीब तबके के लिए सही कदम नहीं उठाया है। यहां मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि निजी उद्यमी देश की छुपी सम्पत्ति को केवल अपनी कमाई के खातिर उच्च कोटि का दोहन करेंगे, बाकी जिसमें उन्हें फायदा नहीं होगा, उसका दोहन नहीं करेंगे। कोयला, सीसा, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, तेल आदि को केवल अपने मुनाफे के लिए उपयोग करेंगे जो देश के हित में नहीं होगा। दूसरी तरफ इन कंपनियों में श्रमिकों की छटनी की जा रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में अराजकता उत्पन्न होने की संभावना है। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि निजी कंपनियों में आरक्षण लागू रखा जाये। मैं एक श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते कहता हूं कि श्रमिक अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। केवल श्रमिक के कारण कोई कंपनी घाटे में नहीं होती, प्रबन्धन की भी त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण उद्योग घाटे में जाते हैं, यह मेरा अनुभव है। इन कंपनियों मे सरकारी हस्तक्षेप एवं निगरानी होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त सभी तथ्यों को गम्भीरतापूर्वक लिया जाए।